Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

Case No.-10/2024

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Basgit Parcha Revision Case No.-10/2024

Gafur Safi..Appellant

Versus

The State of Bihar & Others......................Respondents

Serial No.	Date of order of procedding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	23.8.2025	प्रस्तुत वासगीत पर्चा पुनरीक्षण न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के वासगीत पुनरीक्षण वाद संख्या-02/2020 (अंचल अधिकारी, राघोपुर बनाम गफुर साफी) में दिनांक-22.8.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। अपीलार्थी की ओर से Board Miscellaneous rules 1958 के धारा-10(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद दायर किया गया है। Board Miscellaneous rules 1958 के धारा-10 में अंकित है कि "Commissioners are authorized to issue circular orders to their subordinates on questions of procedure and general practice. A copy of very such circular should, when it relates to revenue matters, be transmitted to the Board of Revenue, and, in other cases to Government". जबकि विपक्षी का कथन है कि बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वास भूमि अधिनियम-1947 के धारा-18 के अनुसार यह वाद सुनवाई योग्य नहीं है। Bihar privilenged persons tenancy Act, 1947 के धारा-18 में स्पष्ट नियमन दिया गया है कि "The orders passed under this Act. shall be final. Subject to the provisions of Section 21, all orders passed by the Collector in any proceeding under this Act shall be final, and no suit shall lie in any Civil Court to vary or set aside any such order except on the ground of fraud or want of jurisdiction." Board Miscellaneous rules 1958 के धारा-3 में अंकित है कि "A higher authority has all the powers of any lower authority and, further may, with or without appeal, modify or reverse any orders passed by lower authority, in a matter primarily with in the competence of the lower authority, unless, by any law, the orders of the lower authority are final." उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं उपस्थापित कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा वासगीत पुनरीक्षण वाद संख्या-02/2020 में दिनांक-22.8.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में Appeal/Revision का प्रावधान निरूपित नहीं है। अतः तद्नुसार इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। LCR निम्न न्यायालय को वापस भेजें। Sd/- 23/8/25. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Sd/- 23/8/25. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा